

धर्म करके  
ईश्वर से  
मांगना पड़ता है  
और कर्म करके ईश्वर  
को देना पड़ता है।  
- अज्ञात



## एक-दूसरे से बनते दिलचस्प रिश्ते

ये दोनों चेहरे पिछले विधानसभा चुनाव में एक साथ थे क्योंकि कभी करीबी दोस्त और फिर प्रबल राजनीतिक विरोधी रहे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने नाटकीय ढंग से एक-दूसरे का हाथ थाम लिया था।

राधा जोशी।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। यहां मतदान बुधवार को होने वाले हैं। इन चुनावों की एक खास बात है विभिन्न परस्पर विरोधी खेमों के एक-दूसरे से बनते दिलचस्प रिश्ते। मुख्य मुकाबला तेजस्वी यादव की अगुआई वाले महागठबंधन और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच है। ये दोनों चेहरे पिछले विधानसभा चुनाव में एक साथ थे क्योंकि कभी करीबी दोस्त और फिर प्रबल राजनीतिक विरोधी रहे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने नाटकीय ढंग से एक-दूसरे का हाथ थाम लिया था। मगर 20 महीने के अंदर नीतीश ने इस दोस्ती से खुद को अलग करते हुए फिर बीजेपी के साथ जाना उचित समझा। दोस्ती और दुश्मनी

का यह पल-पल बदलता रूप इस बार दोनों खेमों के रिश्तों को असहज बनाए हुए है।

बीजेपी ने सहयोगी दल जेडीयू के लिए जो सीटें छोड़ी हैं उन सब पर एलजेपी ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। हालांकि बीजेपी नेतृत्व बार-बार कह चुका है कि पार्टी का गठबंधन जेडीयू के साथ नहीं है, एलजेपी से इन चुनावों में उसका कोई संबंध नहीं है। मगर केंद्र में एलजेपी आज भी एनडीए का हिस्सा बनी हुई है और सीट बंटवारे में टिकट से वंचित हुए कई बीजेपी नेता एलजेपी से किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में इस धारणा का निर्मूल होना मुश्किल है कि असल में बीजेपी ही अपनी बंदूक एलजेपी के कंधे पर रखकर चला रही है। बहरहाल, उसके

नेताओं के स्पष्टीकरण का जमीन पर कितना और कैसा असर हो रहा है, इसका कुछ अंदाजा पहले दौर की वोटिंग का माहौल देखकर भी हो जाएगा।

मुद्दों की बात करें तो सबसे चौंकाने वाली भूमिका बॉलिवुड ऐक्टर सुशांत सिंह की मौत की रही।

बिहार के चुनावों में बिहारी अस्मिता आम तौर पर मुद्दा नहीं बनती, पर सुशांत को न्याय दिलाने की मांग जिस चमत्कारिक ढंग से सभी पार्टियों के अजेंडे में शामिल हो गई, उससे लगा कि बिहारी अस्मिता का सवाल इन चुनावों में छाया रहेगा। लेकिन यह जिस तेजी से उठा था, उसी तेजी से फीका पड़ता गया। आलम यह है कि जेडीयू और बीजेपी भी चुनाव प्रचार में इसका जिक्र नहीं कर रही हैं। दस लाख

सरकारी नौकरियों का वादा कर तेजस्वी यादव ने जरूर बिहार के चुनावों को जाति-धर्म से अलग ठोस जमीनी मुद्दों की ओर मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसके जवाब में बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का वादा कर दिया। ऐसे में तय करना मुश्किल है कि बीजेपी के इस वादे से ज्यादा परेशानी तेजस्वी को होगी या नीतीश कुमार को।

कारण यह कि बीजेपी का बयान आने तक नीतीश कुमार चुनावी मंचों से कई बार तेजस्वी के इस वादे को अव्यावहारिक और असंभव करार दे चुके थे। इस चुनावी महाभारत में कौन किसके साथ खड़ा है और किसका वार दरअसल किसे घायल कर रहा है इसकी जानकारी भी अंतिम तौर पर चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद ही हो सकेगी।

### मतभेद

अशोक वोहरा।

इसमें वर्ण एवं जाति के बीच मतभेद दिखता है। वर्ण व्यवस्था तो हिन्दू धर्म में आरम्भ से है किन्तु जातिप्रथा जैसी कोई भी चीज हिन्दू धर्म में कभी नहीं

### धर्म-दर्शन



रही। अब प्रश्न ये आता है कि यदि वाल्मीकि रामायण में शम्भूक नामक कोई व्यक्ति है ही नहीं तो फिर ये कथा किस प्रकार जनमानस में प्रचलित हुई? इसका उत्तर ये है कि इसे एक सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में बाद में प्रसारित किया गया। और इसे प्रसारित करने का जो साधन बना वो है रामायण का उत्तर कांड। हम सभी को ये बताया गया है कि रामायण में कुल 7 कांड हैं, किन्तु रामायण का उत्तर कांड एक बहुत विवादस्पद खंड है। आइये इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। वे स्वयं उस युग और घटनाओं के साक्षी तो थे किन्तु वाल्मीकि रामायण में उनका बहुत अधिक वर्णन नहीं आता है।

## संपादकीय

### खुद को बदलना होगा

जिस 'नए बिहार' का एक लंबे वक्त से सपना देखा जा रहा है, उसके लिए खुद 'बिहार' को बदलना होगा। यह उम्मीद बेमानी होगी कि बाहर से कोई जादू की छड़ी लेकर आएगा, घुमाएगा और बिहार रातों-रात बदल जाएगा। बिहार के नेताओं को यह मालूम है कि मुद्दों को आगे करके यहां चुनाव नहीं जीते जा सकते। यहां चुनाव जीतने के लिए जाति-धर्म का समीकरण बैठाना ही होगा। लालू यादव एक वक्त बिहार के करिश्माई चेहरा बनकर सिर्फ इसलिए उभरे थे कि उन्होंने जीत का 'माई' (मुस्लिम-यादव) समीकरण तैयार कर लिया था। और यह समीकरण उस वक्त तक अजेय रहा, जब तक कि बीजेपी और जेडीयू ने अपर कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड क्लास का नया समीकरण तैयार नहीं कर लिया। इसके बाद बिहार की पॉलिटिक्स पिछले तीन दशकों से इसी समीकरण के इर्द-गिर्द घूम रही है। ऐसा नहीं कि यह केवल बिहार में हो रहा है, लेकिन बिहार में इसकी जड़ें कुछ ज्यादा गहरी हैं। इस वजह से बिहार के पिछड़ेपन से बाहर आने की कोशिशें परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। 'नए बिहार' की कल्पना तभी साकार हो सकती है, जब जेहनियत में भी बदलाव आए। जाति-धर्म के मकड़जाल से बाहर निकलकर मुद्दों पर आधारित पॉलिटिक्स को तरजीह देनी होगी। नेताओं को इस बात की कोई फिक्र नहीं होगी कि उनकी कोई जवाबदेही भी है। उनकी प्राथमिकता जीत के समीकरण बैठाने तक ही सीमित होगी।

सेकुलरिज्म के प्रतीक के रूप में। इस दरम्यान उन्होंने एक नारा दिया था, जब तक समोसे में आलू रहेगा, बिहार में लालू रहेगा। यानी अब वे बिहार में अपने स्थायित्व को लेकर हद दर्जे तक मुतमर्दन थे।

## लालू ही चुनाव का मुद्दा

नदीम।

वर्ष 1990 में बिहार में जनता दल की जीत के पीछे बेशक वीपी सिंह का करिश्मा था, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में लालू प्रसाद यादव की अपनी जोड़तोड़ रंग लाई थी। लालू प्रसाद यादव वीपी सिंह की पसंद नहीं थे। वीपी तो राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे, अजित सिंह भी वीपी की इस मुहिम में उनके साथ थे, लेकिन लालू यादव खुद के अलावा बिहार में किसी और को मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहते थे।

उस वक्त जनता दल ऊपर से तो देखने में एक था, लेकिन उसके अंदर कई पावर सेंटर थे। लालू ने अपने लिए पहले देवीलाल का समर्थन जुटाया, फिर चंद्रशेखर भी उनके साथ आ गए। देवीलाल ने शरद यादव और मुलायम सिंह यादव को भी लालू के समर्थन में कर लिया। इस दबाव में वीपी सिंह इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायकों के वोट के जरिए होगा। इसी बीच रघुनाथ झा भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर सामने आ गए।

कहा तो यह जाता है कि झा की उम्मीदवारी लालू की रणनीति का हिस्सा थी। खैर लालू यादव अपने मुकाबिल राम सुंदर दास और रघुनाथ झा से ज्यादा विधायकों का समर्थन



जुटाने में कामयाब रहे। शुरुआती दिनों में तो लालू की कोशिश मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करने वाले अलग-अलग पावर सेंटर्स को खुश करने में ही दिखी, लेकिन राम मंदिर के समर्थन में रथ यात्रा पर निकले लालकृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लेने के बाद लालू यादव एक नए अवतार में सबके सामने थे। सेकुलरिज्म के प्रतीक के रूप में। इस दरम्यान उन्होंने एक नारा दिया था, जब तक समोसे में आलू रहेगा, बिहार में लालू रहेगा। यानी अब वे बिहार में अपने स्थायित्व को लेकर हद दर्जे तक मुतमर्दन थे।

लालू के साथ भी वही हुआ। पिछले 15 वर्षों से (20 महीने की एक छोटी सी अवधि को अगर छोड़ दिया जाए, जब उनकी पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार में साझेदार थी) वे बिहार की सत्ता से बाहर चल रहे हैं और वर्ष 2017 से जेल में भी बंद हैं। लेकिन संयोग यह कि 2020 के चुनाव में भी लालू ही मुद्दा बने हुए हैं। सत्तारूढ़ एनडीए का पूरा चुनावी अभियान लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केंद्रित है। एनडीए और खासतौर पर नीतीश कुमार अपने 15 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता में जाने के बजाए 90 से 2005 के लालू प्रसाद यादव के राजकाज को मुद्दा बनाए हुए हैं। यही यह जाहिर करता है कि लालू प्रसाद यादव आज भी बिहार में मुद्दा हैं और एनडीए को सत्ता तक पहुंचने के लिए लालू यादव को पार करना ही होगा।

लालू यादव की अगर आज की तारीख में कोई प्रासांगिकता नहीं होती, तो नीतीश कुमार को उनके खिलाफ अपने चुनावी अभियान को केंद्रित करने की जरूरत भी नहीं होती। बिहार की पॉलिटिक्स में लालू के समोसे में आलू की मानिंद होने का सबूत भी यही है कि विपक्ष जब नीतीश कुमार को उनके 15 साल के शासन पर जवाबदेही के फ्रंट पर लाना चाहता है, तो सत्तारूढ़ दल की तरफ से यह स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि अगर लालू की सत्ता आ गई तो फिर से 'जंगलराज' की वापसी हो जाएगी।

सूदंकु नवताल- 5516				सूदंकु नवताल- 5515 का हल											
5	9	3	8	7	7	4	8	3	9	2	1	5	6		
8	7	1	5		2	6	9	5	7	1	8	4	3		
	2		9	4	3	1	5	4	8	6	7	2	9		
6			2	3	5	5	7	4	8	6	9	3	1	2	
3	8	4	1	7	2	9	8	9	1	2	3	4	6	7	5
2	4	6			1		6	3	2	1	5	7	4	9	8
7		3			8		4	8	7	6	2	5	9	3	1
		5		8	7	3	9	2	6	7	1	3	5	8	4
9	3		2		6	1	1	5	3	9	4	8	2	6	7

### अपना ब्लॉग देश के लिए एक मिसाल बने

**मोहन।** होना तो यह चाहिए था कि लालू कोई चुनावी मुद्दा ही नहीं होते। 15 साल का वक्त इतना लंबा होता है कि सत्तारूढ़ दल को 15 साल के रिपोर्ट कार्ड और अगले पांच साल के विजन के साथ चुनाव मैदान में होना चाहिए था। शायद यह एक नए बिहार की ओर बढ़ता कदम होता। यह सवाल हो सकता है कि यह नसीहत सिर्फ बिहार को ही क्यों? बदलाव के लिए शुरुआत तो किसी को करनी ही होगी। बेहतर होगा कि यह शुरुआत बिहार से हो। जो राज्य बरसों से पिछड़ेपन का दंश झेलता आया हो, वह देश के लिए एक मिसाल बने और बदलाव की राजनीति का नेतृत्व करे। बिहार की पॉलिटिक्स में लालू एक करिश्मा बनकर उभरे थे, लेकिन हर करिश्मे का एक अंत होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार उसी ढर्रे पर चलता रहेगा, जैसा चल रहा है।

